



## प्रेस विज्ञप्ति

### केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट की घोषणा

## महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल एवं एकीकृत सहायता ढांचे के माध्यम से हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा

नई दिल्ली – 01 फरवरी, 2026: हस्तशिल्प नियांत संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) ने माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत किया है। बजट में हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल सहित कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं, जिनका दायरा निर्माण, नियांत, कौशल विकास, डिजिटल अवसंरचना एवं ग्रामीण सशक्तिकरण विस्तृत है।

बजट घोषणाओं का स्वागत करते हुए ईपीसीएच के अध्यक्ष डॉ. नीरज खन्ना ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 में नियांत वृद्धि के लिए एक रणनीतिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिसमें एमएसएमई, अवसंरचना, डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन और क्षेत्र-विशिष्ट प्रोत्साहनों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट 2026 में हस्तशिल्प क्षेत्र हेतु कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:

- महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल:** खादी, हथकरघा एवं हस्तशिल्प को प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, ब्रांडिंग और वैश्विक बाजार से जोड़ने हेतु एक पहल; जिससे बुनकरों, ग्रामोद्योग, ओडीओपी उत्पादों और ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा।
- कपड़ा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम:** एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जिसमें मशीनरी के लिए कैपिटल सपोर्ट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और कॉमन टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर के जरिए पारंपरिक क्लस्टर का मॉडर्नाइज़ेशन शामिल है; मौजूदा स्कीम को मजबूत करने के लिए एक नेशनल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम; टेक्स-इको के तहत सस्टेनेबल प्रोडक्शन को बढ़ावा देना; और समर्थ 2.0 के जरिए स्किल अपग्रेडेशन।
- “चैंपियन एमएसएमई” का निर्माण एवं सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन:** तरलता सहायता के तहत (टीआरईडीएस (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमई) और एमएसएमई के लिए वित्त तक तेज और सस्ती पहुंच को सक्षम करने के लिए टीआरईडीएस के साथ सरकारी ई मार्केटप्लेस (जीईएम) को जोड़ा गया है।
- पुराने औद्योगिक क्लस्टरों का कायाकल्प:** 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने के लिए एक योजना शुरू की गई है ताकि बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से उनकी लागत प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता में सुधार किया जा सके।
- डिज़ाइन एजुकेशन और इनोवेशन:** डिज़ाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने और भारतीय डिज़ाइनरों की कमी को दूर करने के लिए पूर्वी इलाके में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बनाया जाएगा, जिससे हस्तशिल्प और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए टैलेंट इकोसिस्टम बनेगी।
- कैपिटल गुड्स कैपेबिलिटी:** सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज द्वारा दो जगहों पर हाई-टेक टूल रूम बनाए जाएंगे, जो हाई-प्रिसिजन कंपोनेंट्स के डिज़ाइन, टेस्टिंग और मैन्युफैक्चर के लिए डिजिटली इनेबल्ड ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो होंगे।
- ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज पर टीसीएस को रैशनलाइज़ेशन:** विदेश यात्रा पैकेजों पर टीसीएस बिना किसी थ्रेशहोल्ड सीमा के घटाकर 2% किया गया।
- कस्टम्स प्रक्रिया – ट्रस्ट-बेस्ड सिस्टम्स:** टियर-II और टियर-III ऑथराइज़ड इकोनॉमिक ऑफेरेटर्स के लिए ड्यूटी डेफरल पीरियड 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया।
- ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस:** कई सरकारी एजेंसियों से कार्गो क्लीयरेंस अप्रूवल एक सिंगल, इंटीग्रेटेड डिजिटल विंडो के जरिए प्रोसेस किए जाएँगे।

- **स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन फ्लेक्सिबिलिटी:** एक विशेष “चन-टाइम” उपाय के तहत, वैश्विक व्यापार व्यवधानों के कारण क्षमता उपयोग की चुनौतियों को देखते हुए, एसईजेड की पात्र विनिर्माण इकाइयों को कन्सेशनल ड्यूटी रेट्स पर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बिक्री की अनुमति दी जाएगी।
- **ई-कॉमर्स के माध्यम से नए निर्यात अवसर:** कूरियर निर्यात में प्रति कंसाइनमेंट ₹10 लाख की वैल्यू कैप हटाना तथा रिटर्न/रिजेक्टेड कंसाइनमेंट्स की प्रक्रियाओं का सरलीकरण।

ईपीसीएच के अध्यक्ष डॉ. नीरज खन्ना ने आगे कहा, “केंद्रीय बजट 2026-27 भारत के हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की शुरुआत खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार से जोड़ने, ब्रांडिंग और कौशल विकास के माध्यम से मजबूत करने का एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट जैसी व्यवस्थाएँ तथा उद्यमों की रेजिलिएंस और स्केल बढ़ाने वाली पहलें हस्तशिल्प क्षेत्र की दीर्घकालिक वृद्धि में योगदान देंगी और माननीय प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत’ के विजय के अनुरूप समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास के व्यापक लक्ष्य को समर्थन देंगी।”

ईपीसीएच के महानिदेशक की भूमिका में मुख्य संरक्षक और आईईएमएल के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार ने कहा, “केंद्रीय बजट 2026-27 ने ग्लोबल ट्रेड में रुकावटों के दौर में एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए एक प्रैक्टिकल और समय पर कदम उठाया है। स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (एसईजेड) में एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कन्सेशनल ड्यूटी रेट्स पर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बिक्री की एक-बारगी विशेष अनुमति, क्षमता उपयोग की चुनौतियों को दूर करने में मदद करेगी और उत्पादन निरंतरता तथा रोजगार बनाए रखने में सहायक होगी।”

डॉ. कुमार ने आगे कहा, “सरकार की ट्रस्ट-बेस्ड कस्टम्स व्यवस्थाएँ और कार्गो किलयरेंस के लिए सिंगल इंटीग्रेटेड डिजिटल विंडो की दिशा में कदम, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को मजबूत करते हैं और सप्लाई चेन में रुकावटें घटाते हैं। हस्तशिल्प जैसे निर्यात-लिंक्ड क्षेत्रों के लिए ये उपाय ऑपरेशनल रेजिलिएंस बढ़ाते हैं, तेज़ ऑर्डर फुलफिलमेंट में सहायता करते हैं तथा घेरेलू और वैश्विक बाजारों में स्थायी प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए मजबूत आधार तैयार करते हैं।”

ईपीसीएच के उपाध्यक्ष श्री सागर मेहता ने कहा, “एसएमई ग्रोथ फंड के माध्यम से ‘चैंपियन एमएसएमई’ बनाने तथा ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के जरिए तरलता समर्थन बढ़ाने पर बजट का फोकस हमारे हस्तशिल्प उद्यमों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा। 200 लिंगों सी औद्योगिक क्लस्टरों के रिवाइवल से पारंपरिक हस्तशिल्प हब्स का आधुनिकीकरण होगा और घेरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।”

ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक श्री राजेश रावत ने कहा, “इस बजट में घोषित डिजिटल इंटीग्रेशन पहलें और ट्रस्ट-बेस्ड कस्टम्स सिस्टम हमारे निर्यातकों के लिए लेन-देन की लागत और समय को काफी कम कर देंगे। किलयरेंस के लिए सिंगल डिजिटल विंडो सरकार की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान की स्थापना से एक ऐसा कुशल कार्यबल तैयार होगा, जो पारंपरिक कारीगरी को समकालीन डिज़ाइन संवेदनाओं से जोड़ सकेगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के कौशल विकास और गुणवत्ता सुधार पर केंद्रित प्रावधानों के साथ मिलकर ये उपाय भारतीय हस्तशिल्प की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएँगे तथा देशभर के लाखों कारीगरों की सतत आजीविका सुनिश्चित करने में सहायक होंगे।”

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद देश से हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने और देश के विभिन्न शिल्प समूहों में होम, लाइफस्टाइल, टेक्स्टाइल, फर्नीचर और फैशन ज्वेलरी एवं एक्सेसरीज के उत्पादन में लगे लाखों शिल्पकारों के प्रतिभाशाली हाथों के जादू की ब्रांड छवि बनाने के लिए एक नोडल संस्थान है। ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक श्री राजेश रावत ने बताया कि वर्ष 2024-25 के दौरान हस्तशिल्प का कुल निर्यात 33,123 करोड़ रुपये (3,918 मिलियन अमेरिकी डॉलर) रहा।

**विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:**

श्री राजेश रावत, कार्यकारी निदेशक, ईपीसीएच

+91-9810423612



## **UNION BUDGET 2026-27 ANNOUNCED BY THE UNION FINANCE MINISTER**

### **Historic Boost for Handicrafts Sector Through Mahatma Gandhi Gram Swaraj Initiative and Integrated Support Framework**

**New Delhi – 01<sup>st</sup> February, 2026:** The Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH) has welcomed the Union Budget 2026-27 presented by Hon'ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman, which introduces landmark initiatives for the handicrafts sector, including the Mahatma Gandhi Gram Swaraj Initiative and comprehensive support measures spanning manufacturing, exports, skilling, digital infrastructure and rural empowerment.

Welcoming the budget announcements **Dr. Neeraj Khanna, Chairman - EPCH** said that the Union Budget 2026 outlines a strategic framework for increasing exports, focusing on MSMEs, infrastructure, digital trade facilitation and sector-specific incentives. The Budget 2026 contains some benefits for handicrafts sector which are indicated below:

- **Mahatma Gandhi Gram Swaraj Initiative:** An initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts through training, skilling, quality improvement, branding and global market linkages, benefiting weavers, village industries, ODOP products and rural youth.
- **Integrated Programme for the Textile and Handicrafts Sector:** An integrated programme covering modernisation of traditional clusters through capital support for machinery, technology upgradation and common testing and certification centres; a National Handloom and Handicraft Programme for strengthening existing schemes; promotion of sustainable production under Tex-Eco; and skilling upgradation through Samarth 2.0.
- **Creation of “Champion MSMEs” and Support to Micro Enterprises:** Liquidity support measures to include credit guarantee for invoice discounting on Trade Receivables Discounting System (TReDS) through Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) and linkage of Government e Marketplace (GeM) with TReDS to enable faster and cheaper access to finance for MSMEs.
- **Rejuvenation of Legacy Industrial Clusters:** A scheme has been introduced to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation.
- **Design Education and Innovation:** A new National Institute of Design will be established in the eastern region to boost design education and address the shortage of Indian designers, creating a talent pipeline for the handicrafts and creative industries.
- **Capital Goods Capability:** Hi-Tech Tool Rooms to be set up by Central Public Sector Enterprises (CPSEs) at two locations as digitally enabled automated service bureaus for design, testing and manufacture of high-precision components.
- **Rationalisation of TCS on Overseas Tour Programme Packages:** Tax Collected at Source (TCS) on overseas tour programme packages reduced to 2 % without any threshold limit.
- **Customs Process – Trust-Based Systems:** Duty deferral period for Tier-II and Tier-III Authorised Economic Operators enhanced from 15 days to 30 days.

- **Ease of Doing Business:** Cargo clearance approvals from multiple government agencies to be processed through a single, integrated digital window.
- **Special Economic Zone Flexibility:** As a special one-time measure, eligible manufacturing units in SEZs will be allowed to sell to the Domestic Tariff Area (DTA) at concessional duty rates, addressing capacity utilization concerns due to global trade disruptions.
- **New Export Opportunities through E-commerce:** Removal of the ₹10 lakh per consignment value cap on courier exports and simplification of procedures for returns and rejected consignments.

**Dr. Neeraj Khanna, Chairman - EPCH** further shared that “The Union Budget 2026-27 marks a transformative moment for India's handicrafts sector. The introduction of the Mahatma Gandhi Gram Swaraj Initiative represents an integrated approach to strengthening khadi, handloom, and handicrafts through enhanced global market linkages, branding, and skill development. Provisions such as the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) and initiatives aimed at improving enterprise resilience and scale will contribute to long-term growth of the handicrafts sector and support the broader objective of inclusive and sustainable economic development in line with the Hon'ble Prime Minister's vision of Viksit Bharat.”

**Dr. Rakesh Kumar, Director General in the role of Chief Mentor, EPCH and Chairman, IEML** shared that “The Union Budget 2026-27 has taken a pragmatic and timely step to support export-oriented manufacturing during a phase of global trade disruptions. The special one-time flexibility for eligible manufacturing units in Special Economic Zones (SEZs) to sell into the Domestic Tariff Area (DTA) at concessional duty rates will help address capacity utilisation challenges and enable units to maintain production continuity and employment. “This, combined with the Government's trust-based customs measures and the move towards a single integrated digital window for cargo clearances, strengthens ease of doing business and reduces friction across the supply chain. For export-linked sectors such as handicrafts, these interventions improve operational resilience, support faster order fulfilment, and create a stronger foundation for sustained competitiveness in both domestic and global markets.” Dr. Kumar added further.

**Shri Sagar Mehta, Vice Chairman – EPCH** said that “The Budget's focus on creating Champion MSMEs through a SME Growth Fund and enhanced liquidity support through TReDS (Trade Receivables Discounting System) will be a game-changer for our handicraft enterprises. The revival of 200 legacy industrial clusters will now modernize traditional handicraft hubs and will improve competitiveness in domestic as well as international market.”

**Shri Rajesh Rawat, Executive, Director – EPCH** said that “The digital integration initiatives and trust-based customs systems announced in this Budget will significantly reduce transaction costs and time for our exporters. The single digital window for clearances demonstrates the government's commitment to ease of doing business. Through the establishment of a National Institute of Design in the eastern region, a skilled workforce will be created that will combine traditional craftsmanship with contemporary design sensibilities. Combined with the Mahatma Gandhi Gram Swaraj Initiative's focus on skill development and quality improvement, these measures will enhance the global competitiveness of Indian handicrafts while ensuring sustainable livelihoods for millions of artisans across the country”.

Export Promotion Council for Handicrafts is a nodal institution for promotion of exports of handicrafts from the Country and create brand image of magic of the gifted hands of millions of craftspersons engaged in production of home, lifestyle, textiles, furniture and fashion jewellery & accessories products in different craft clusters of the Country. The overall Handicrafts exports during the year 2024-25 was Rs. 33,123 Crores (US \$ 3,918 Million) informed by Shri Rajesh Rawat, Executive Director-EPCH.

---

**For more information please contact:**

Shri Rajesh Rawat, Executive Director, EPCH  
+91-9810423612

Encl: Hindi, English version